

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

CONFUSED ABOUT CAREER!

Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?

Whether to Study in India or Abroad?

What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?

Should I consider Computer or Mechanical Engineering?

What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?

Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?

Do I have the aptitude for Architecture and Designing?

Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9317776662, 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.

प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व सीएम सहित 200 से ज्यादा यात्रियों की मौत

एयर इंडिया के विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई यात्री था सवार; गृहमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना

गांधीनगर, अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 200 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई। 232 यात्रियों और 10 क़्रू मेंबर्स की लेकर उड़ान भरने वाला यह विमान दोपहर 1:17 बजे लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही नीचे उतर गया और बीजे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विमान हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किजरापु, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद थे।

टाटा समूह ने हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को एक करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा की। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों और उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।

पैसेंजर्स की लिस्ट आई सामने

विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई यात्री सवार थे। वहीं, एयर इंडिया यात्रियों और एयर इंडिया कर्मचारियों के परिजनों के लिए अहमदाबाद के लिए दिल्ली और मुंबई से एक-एक राहत उड़ानें आयोजित कर रही हैं। दिल्ली और मुंबई में यात्रियों और कर्मचारियों के परिजन जो इन उड़ानों पर यात्रा करना चाहते हैं, वे हमारी हॉटलाइन 1800 5691 444 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जो लोग अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से आ रहे हैं और यात्रा करना चाहते हैं, वे हमारी हॉटलाइन +91 8062779200 पर कॉल कर सकते हैं।

घनी आबादी वाला था इलाका

एयर इंडिया के बोइंग 787 डीमलाइनर विमान (एआई171) का मलबा बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में चिकित्सकों के छात्रावास व आवासीय क्वार्टरों के आसपास बिखरा हुआ है। गुजरात के इतिहास में सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक इस विमान हादसे के बाद वायरल हुए वीडियो में मलबे में झुलसे हुए शव भी दिखाई दे रहे हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद 242 यात्रियों की लेकर अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनास्थल के आसपास का इलाका घनी आबादी वाला है।

गुजरात सरकार ने मांगे डीएनए सैपल

गुजरात सरकार ने शवों की पहचान के लिए प्लेन में सवार लोगों के परिजनों से डीएनए सैपल देने की अपील की है। हादसा इतना भयानक था कि कई शवों की पहचान करना मुश्किल हो गया है। हादसे में कई स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के असरवा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों को लाया गया है। यहां उन्होंने घायल लोगों से बातचीत की।

क्रैश से पहले पायलट ने दिया था सिग्नल...

डीजीसीए रिपोर्ट से सबसे महत्वपूर्ण खुलासे में से एक ये है कि पायलटों ने उड़ान भरने के तुरंत बाद "मेडे" कॉल जारी किया था। मेडे कॉल विमानन (और समुद्री) में इस्तेमाल किया जाने वाला सर्वोच्च प्राथमिकता वाला अंतरराष्ट्रीय संकेत का संकेत है जिसका अर्थ है मेरी मदद करो।

प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद में हुई दुखद घटना पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी ने पूरे देश को स्तब्ध और दुखी कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह घटना इतनी हृदय विदारक है कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मोदी ने कहा कि वे प्रभावित लोगों को त्वरित एवं प्रभावी सहायता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं।

राष्ट्रपति मुर्मू ने जताई संवेदना

अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद राष्ट्रपति ने अपनी संवेदना जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर अत्यंत व्यथित हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे के बारे में जानकर मैं बहुत व्यथित हूँ। यह एक हृदय विदारक आपदा है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं। इस अवर्णनीय दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है।

विमान हादसे में जिंदा बचा एक शख्स

एयर इंडिया विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रुपाणी समेत 200 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि, विमान में सफर कर रहा एक यात्री जिंदा बच गया। इसे चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने अस्पताल में विश्वास कुमार रमेश से मुलाकात की। विश्वास एयर इंडिया की फ्लाइट में 11ए सीट पर बैठकर लंदन जा रहे थे। दुर्घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 40 वर्षीय विश्वास कुमार ने बताया, 'जब मैं उठा तो मेरे चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं। मैं डर गया। मैं खड़ा हुआ और भागा। मेरे चारों तरफ विमान के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उड़ान भरने के तीस सेकंड बाद तेज आवाज हुई और फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह सब बहुत जल्दी हुआ।' विश्वास के सीने, आंखों और पैरों पर चोट आई है और उनका इलाज चल रहा है।

पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे विजय रुपाणी

गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री रहे विजय रुपाणी उन 200 से ज्यादा लोगों में शामिल हैं, जिनकी मौत एयर इंडिया के विमान हादसे में हुई है। यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। यह हादसा उस समय हुआ, जब विमान संख्या एआई-171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही मेघानीनगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने विजय रुपाणी के निधन की पुष्टि की है।

नागरिक उड्डयन मंत्री बोले- हादसे की जांच होगी

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किजरापु एयर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। स्थिति का जायजा लेने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि हादसे की जांच होगी, मौत का आंकड़ा बताना फिलहाल मुश्किल है। मोहन नायडू किजरापु ने कहा कि हम निष्पक्ष और गहन जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि यह घटना क्यों हुई। हमें अभी भी संख्या का पता लगाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह जानकर बहुत दुख हुआ कि (भाजपा नेता) विजय रुपाणी भी वहां मौजूद थे, साथ ही अन्य नागरिक भी थे। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस दुखद और भयावह घटना से पूरी तरह हिल गया हूँ। मैं अभी भी सदमे में हूँ। प्रधानमंत्री ने मुझे फोन करके घटनास्थल पर आने को कहा है। इस समय मैं सिर्फ यात्रियों और उनके परिवारों के बारे में सोच सकता हूँ। बचाव कार्य में कई एजेंसियां लगी हुई हैं। मैं अभी संख्या के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हम हरसंभव मदद कर रहे हैं।

तीन नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण 19 लाख रुपये का था इनाम

रायपुर, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 19 लाख रुपये के इनामो तीन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के अनुसार, यह घटनाक्रम 2 जून को राज्य के सुकमा जिले में 16 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के कुछ सप्ताह बाद हुआ है। इनमें से छह नक्सलियों पर सामूहिक रूप से 25 लाख रुपये का इनाम था। इनमें से नौ नक्सली चित्तलानार पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत केरलापंडा ग्राम पंचायत के थे। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को पूर्व बस्तर डिवीजन में कंपनी नंबर छह में सक्रिय नक्सली भीमा उर्फ ठोल् उर्फ दिनेश पोंडियाम (40) ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने बताया कि उस पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित है। उन्होंने बताया कि इससे पहले मंगलवार को जिले में दो महिला नक्सली सुकली कोराम उर्फ सपना और देवली मंडावी ने भी आत्मसमर्पण किया। अधिकारियों ने बताया कि सुकली पर आठ लाख तथा देवली पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित है। उन्होंने बताया कि अबुलमाडू क्षेत्र और नारायणपुर जिले में लगातार किए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर तथा नक्सली संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेदों से परेशान होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने पर नक्सलियों को 50 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया है तथा उन्हें नक्सल उन्मूलन नीति के तहत मिलने वाली सुविधाएं दिलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि जिले में इस वर्ष कुल 104 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण किया है।

सीएम मान और केजरीवाल ने राजस्व सुधारों के लिए एक और क्रांतिकारी कदम उठाया

लोगों को अब व्हाट्सएप पर मिलेगी जमाबंदी

इंतकाल- रपट एंट्री और फर्द बदर की सेवाएं भी अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगी

• जालंधर ब्रीज, अमृतसर

पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के 'ईजी जमाबंदी' पोर्टल की शुरुआत की, जिसके साथ पंजाब ने अपने नागरिकों को भ्रष्टाचार मुक्त, सुचारू, पारदर्शी रहित और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने में सफलता का नया मुकाम हासिल किया है। दोनों नेताओं ने कहा कि इस पहल के साथ राजस्व विभाग की प्रमुख सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रिया से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इन सेवाओं से हर साल लाखों लोगों का सीधा संबंध होता है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले पंजाब ने 'ईजी रजिस्ट्री' की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य संपत्ति रजिस्ट्री को सरल और पारदर्शी बनाना तथा भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करना है। भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मोहाली में 'ईजी रजिस्ट्री' का उपक्रम शुरू किया था और यह लोगों के लिए बड़ी सफलता साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने पूरे जिले से भ्रष्टाचार की एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई, जो इस पहल की शानदार सफलता को दर्शाता है।

दोनों नेताओं ने कहा कि इस 'ईजी रजिस्ट्री' को 15 जुलाई तक पूरे पंजाब में लागू कर दिया जाएगा। दोनों नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया था और आज यहां से शुरू हुआ 'ईजी जमाबंदी' पोर्टल का क्रांतिकारी प्रयास हमारी सरकार की ईमानदारी, नेक नीयत, पारदर्शिता और जन-हितैषी उपक्रमों को दर्शाता है। भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह पोर्टल लोगों को पांच प्रमुख सेवाएं प्रदान करेगा, जिनमें व्हाट्सएप पर जमाबंदी प्राप्त करना, इंतकाल करवाना, रपट एंट्री और फर्द बदर (भूमि रिकॉर्ड में सुधार) के लिए ऑनलाइन सेवाएं शामिल

हैं। इसका विस्तार से उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप के माध्यम से जमाबंदी प्राप्त करने का निर्णय लोगों को बड़े पैमाने पर सुविधा प्रदान करेगा, क्योंकि हर साल 40 लाख लोगों को भूमि रिकॉर्ड की फर्द (जमाबंदी) प्राप्त करने के लिए या तो अपने पटवारी के पास चक्कर काटने पड़ते थे या फर्द केंद्रों पर जाना पड़ता था। हालांकि, दोनों नेताओं ने कहा कि अब भूमि रिकॉर्ड के लिए पटवारी के पास जाने, कतारों में खड़े होने या रिश्तत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को केवल 'ईजी वेबसाइट' पर जाकर अपने विवरण दर्ज करने हैं और उन्हें जमाबंदी की प्रति मुफ्त में मिल जाएगी। भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस जमाबंदी पर डिजिटल हस्ताक्षर होंगे और इसमें व्यूआर कोड भी होगा, जिसके माध्यम से कोई भी भूमि रिकॉर्ड की सत्यता की जांच के लिए व्यूआर कोड को स्कैन कर सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब के 99 प्रतिशत गांवों के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर दिया है, सभी भूमि रिकॉर्ड इस सेवा के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं और साथ ही बचे हुए गांवों को भी अगले दो महीनों में डिजिटाइज कर दिया जाएगा।

द्वैवलिंग का नहीं है ज्यादा बजट? कम पैसों में ट्रिप को यादगार बना देंगे ये बजट फ्रेंडली टिप्स



अगर आप दिल्ली के आसपास घूमने वाली जगह तलाश रहे हैं, जहां आप कम पैसों में ज्यादा मजा कर पाएं तो इस खबर में आज आपको कुछ ऐसे बजट फ्रेंडली ट्रैवलिंग टिप्स मिलेंगे, जो आपकी यात्रा को ना सिर्फ यादगार बल्कि मस्ती से भरपूर भी...

BAD HABITS

इन आदतों की वजह से ही आपको हल्के में लेते हैं लोग, इज्जत तो छोड़ो उड़ाते हैं मजाक

कई लोगों में कुछ आदतें होती हैं जो उनकी पूरी पर्सनेलिटी को खराब करती हैं। इन्हीं की वजह से लोग उनकी कोई बात सीरियस नहीं लेते और ना ही ऐसे लोगों की कोई खास इज्जत होती है।



• जालंधर ब्रीज . फीचर

कौन नहीं चाहता कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनें, उसे अहमियत दें और उसकी सलाह मानें। लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता है। अक्सर ऐसा देखने को मिल जाता है कि कुछ लोगों की बातों को तो लोग बहुत तवज्जो देते हैं, वहीं कुछ लोग चाहे जितनी भी जरूरी बात कर रहे हों उन्हें खास महत्व नहीं दिया जाता। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारे व्यवहार में मौजूद छोटी-छोटी आदतें, हमारी छवि को मजबूत या कमजोर बना सकती हैं। चलिए जानते हैं वो कौन सी आदतें हैं, जिनकी वजह से इंसान की छवि कमजोर हो जाती है और लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते।

हर बात में हंसी-मजाक करना

यूं तो हंसते-मुस्कुराते रहना अच्छा होता है, लेकिन हर बात में हंसी-मजाक करना आपकी छवि को कमजोर बना सकता है। हंसी-मजाक करने से व्यक्ति सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बन सकता है, लेकिन जब यही आदत हद से ज्यादा हो जाए तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। हर बात पर मजाक उड़ाना, गंभीर विषयों को भी हंसी में ढाल देना, ये सारी आदतें व्यक्ति की छवि को कमजोर बना देती हैं। ऐसे में लोगों को लगने लगता है कि आपसे सिर्फ हंसी-मजाक की बातें की जा सकती है, किसी गंभीर विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती।

बार-बार अपने डिसीजन बदलना

कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने द्वारा लिए गए डिसीजन पर खड़े नहीं रह पाते और बार-बार अपने डिसीजन चेंज करते रहते हैं। या यूं कहें कि उन्हें अपने द्वारा लिए गए फैसले पर ही विश्वास नहीं होता है। कभी कुछ कहना और थोड़ी देर बाद कुछ और कहना, ऐसी आदत की वजह से, दूसरों को उस व्यक्ति की पर्सनालिटी वाक लगने लगती है। ऐसे में लोग आसानी से उन पर यकीन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उस व्यक्ति की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता।

बहुत अधिक दिखावा करना

डिस्कलेमर : यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।

द्वैवलिंग.नॉलेज.हेल्थ

घर का खाना इतना क्यों पसंद करते हैं भारतीय? एक्सपर्ट बता रही इससे जुड़े दिलचस्प किस्से



• जालंधर ब्रीज . फीचर

एक अध्ययन के मुताबिक 80 प्रतिशत भारतीय माह में सिर्फ एक बार घर से बाहर खाना खाते हैं। जबकि बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। इसी संदर्भ में स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत की पोस्ट खूब वायरल हुई। निखिल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि सिंगापुर जैसे देशों की तुलना में जहां लोग घर का खाना कभी नहीं बनाते, भारत में लोग अभी भी घर के खाने के दीवाने हैं। बिेशक भारतीयों के लिए बाहर खाना खाना आज भी खास मौकों के लिए ही तय किया जाता है और यह बस सुनी-सुनाई बात भर नहीं है।

स्विगी कंपनी द्वारा हाउ इंडिया ईट्स, 2024 नाम से प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारतीय हर माह सिर्फ पांच बार बाहर का खाना खाते हैं। यह आंकड़ा अन्य देशों चीन (33), अमेरिका (27) और सिंगापुर (19) की तुलना में बहुत कम है। इन आंकड़ों की सचाई की बानगी हमारे देश के टीयर-2 और 3 शहर भी हैं, जहां बाहर का खाना या बाहर जाकर खाना कुछ खास मौकों पर ही किया जाता है।

स्विगी, जोमैटो, फूड पांडा जैसे खाने की तुरंत डिलिवरी वाले दौर में घर का खाना कैसे हमारे दिलों पर राज कर रहा है, यह दुनियाभर के लिए आश्चर्य है। बिना रसोई के भारतीय घरों की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वह सेहत का स्रोत है, तो मां की याद भी और दादी-नानी का प्यार भी। खाद्य मानवविज्ञानियों की मानें तो घर के खाने के प्रति हमारे रुझान के लिए सेहत और हाइजीन जैसे मुद्दे ही नहीं, बल्कि इसके लिए पितृसत्ता, जाति व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रभाव भी जिम्मेदार होते हैं।

सबको पसंद घर का खाना : घर के खाने को घर-घर में जगह मिलने के पीछे कुछ सामाजिक-सांस्कृतिक कारण भी जिम्मेदार हैं। मसलन घर के बने खाने को हम पवित्र मानते हैं। क्योंकि आज भी भारतीय घरों की आम कहानी है कि घर की महिलाएं ही खाना बनाती हैं और पूरा परिवार खाता

यूट्यूब पर वीडियो देख-देखकर अब हर उम्र के लोग देसी से लेकर विदेशी खानपान तक अपनी रसोई में बना रहे हैं। अपने हाथों से खाना बनाने के इस उभरते शौक के लिए पोषण, बचत से लेकर प्रोसेस्ड फूड को घर-घर में जगह मिलने के पीछे कुछ सामाजिक-सांस्कृतिक कारण भी जिम्मेदार हैं। मसलन घर के बने खाने को हम पवित्र मानते हैं। क्योंकि आज भी भारतीय घरों की आम कहानी है कि घर की महिलाएं ही खाना बनाती हैं और पूरा परिवार खाता

• जालंधर ब्रीज . हेल्थ केयर

आज कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है। कुछ ऑर्डर कर लें क्या? वोकेंड है, आज बाहर डिनर करना तो बनता है। यकीनन जुबान के चटखारे आपको बाहर पके मसालेदार खाने की ओर खींचते हैं, पर, यकीन मानिए घर का खाना आपके लिए हमेशा से फायदे का सौदा रहा है। जहां बाहर का खाना दबे पांव आपको तमाम बीमारियों की ओर ले जाता है, वहीं मां के हाथ के बने घर के खाने में सिर्फ सुकून ही नहीं बल्कि सेहत भी होती है। घर के खाने की खासियत है कि इसमें आप अपने स्वाद और सेहत के हिसाब से पोषण और स्वाद जोड़ सकते हैं। वहीं, बाहर का खाना आपकी सेहत और पैसों पर सिर्फ और सिर्फ बट्टा लगाकर का काम करता है। इस बात की तसदीक विश्व स्वास्थ्य संगठन भी करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानें तो दुनिया में हर साल बाहर का खाना खाने से लगभग 60 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं और उनमें से 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत तक हो जाती है। अब आप कहेंगी ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो हर शख्स बीमार ही पड़ा होता।

इस बाबत आहार एक्सपर्ट कहती हैं कि बाहर के खाने से सब बीमार हो जाएं जरूरी नहीं, पर इस बात की आशंका ज्यादा होती है। बाहर की रसोई पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। वहां का खाना कितनी स्वच्छता से बनाया जा रहा है, कौन से उत्पाद इस्तेमाल हो रहे हैं, खाना ताजा है या पहले से रखे खाने में तड़का लगाकर परोसा जा रहा है, हम नहीं जानते। हम कहते हैं कि खाने को छोटे-छोटे मीलस्टे में बांटेकर खाना चाहिए। पर, होटल का खाना हम एक बार ढेर सारा खा लेते हैं, जिसके चलते कैलोरी का सारा गणित बिगड़ जाता है। साथ ही ज्यादा तेल-मसाले का लंबे समय तक सेवन भी हमारे पाचन को बिगाड़ देता है। नतीजा, अलग-अलग तरीके की परेशानियां। लिहाजा, बेहतर होगा कि बाहर के खाने की जगह घर के खाने को तरजोह दें। घर पर हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से पकवानों में स्वाद के साथ पोषण भी डाल सकते हैं। घर पर बना खाना बाहर के खाने की तुलना में किफायती भी होता है। **बाहर का खाना यानी ज्यादा कैलोरी :** जब आप स्वाद की तलाश में रेस्टोरेंट के मैनु से ऑर्डर करती हैं, तो खुशी

• जालंधर ब्रीज . फीचर

बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी हैं लेकिन आप अगर बजट कम होने की वजह से अभी तक कोई ट्रैवल ट्रिप प्लान नहीं कर पाए हैं तो आज हम आपकी टेंशन को दूर करने वाले हैं। जी हां इस खबर में आज आपको कुछ ऐसे बजट फ्रेंडली ट्रैवलिंग टिप्स मिलेंगे, जो आपकी यात्रा को ना सिर्फ यादगार बल्कि मस्ती से भरपूर भी बनाए रखेंगे। आइए जानते हैं कैसे ट्रैवलिंग को छोटे-छोटे ट्रिप्स के साथ बजट फ्रेंडली बनाया जा सकता है।

पहले से ही कर लें बुकिंग

फ्लाइट्स, ट्रेन टिकट और होटल की बुकिंग 3 महीने पहले करने से वो आपको सस्ते दाम पर मिल सकती है। मंगलवार या बुधवार को भी बुकिंग करने पर कीमतें कम हो सकती हैं। बुकिंग करने के लिए Skyscanner या Google Flights जैसे टूल्स का उपयोग करें। रहने के लिए बजट की जगह पसंद करें होटल की जगह आप ठहरने के लिए हॉस्टल, Airbnb, या गेस्टहाउस चुन सकते हैं। ये सस्ते होने के साथ स्थानीय अनुभव भी देते हैं। इसके लिए आप Booking.com या Hostelworld पर सस्ते ऑप्शन ढूंढ सकते हैं।

लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करें

अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर वहां घूमने के लिए टैक्सी या कार की जगह लोकल बस, मेट्रो जैसे स्थानीय ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। यह सस्ता और पर्यावरण के लिए भी बेहतर रहता है। ऐसा करते हुए किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए पहले ही अपना होमवर्क पहले से ही करके जाएं। खुद खाना बनाएं या स्थानीय खाए रेस्तरां की जगह स्थानीय बाजारों से सामग्री खरीदकर खुद ही खाना बना लें। आजकल कई होमस्टे में यह सुविधा मौजूद होती है।

जैसे टूल्स का उपयोग करें। रहने के लिए बजट की जगह पसंद करें होटल की जगह आप ठहरने के लिए हॉस्टल, Airbnb, या गेस्टहाउस चुन सकते हैं। ये सस्ते होने के साथ स्थानीय अनुभव भी देते हैं। इसके लिए आप Booking.com या Hostelworld पर सस्ते ऑप्शन ढूंढ सकते हैं।

लेकिन आप अगर खाना बाहर खा रहे हैं तो लोकल स्ट्रीट फूड या छोटे ढाबों पर जाना बिल्कुल ना भूलें। यहां आपको ट्रेडिशनल फूड बेहद कम दाम में मिलेगा।

घर का खाना इतना क्यों पसंद करते हैं भारतीय? एक्सपर्ट बता रही इससे जुड़े दिलचस्प किस्से

• जालंधर ब्रीज . फीचर

जैसे टूल्स का उपयोग करें। रहने के लिए बजट की जगह पसंद करें होटल की जगह आप ठहरने के लिए हॉस्टल, Airbnb, या गेस्टहाउस चुन सकते हैं। ये सस्ते होने के साथ स्थानीय अनुभव भी देते हैं। इसके लिए आप Booking.com या Hostelworld पर सस्ते ऑप्शन ढूंढ सकते हैं।

लेकिन आप अगर खाना बाहर खा रहे हैं तो लोकल स्ट्रीट फूड या छोटे ढाबों पर जाना बिल्कुल ना भूलें। यहां आपको ट्रेडिशनल फूड बेहद कम दाम में मिलेगा।

जैसे टूल्स का उपयोग करें। रहने के लिए बजट की जगह पसंद करें होटल की जगह आप ठहरने के लिए हॉस्टल, Airbnb, या गेस्टहाउस चुन सकते हैं। ये सस्ते होने के साथ स्थानीय अनुभव भी देते हैं। इसके लिए आप Booking.com या Hostelworld पर सस्ते ऑप्शन ढूंढ सकते हैं।

डिस्कलेमर : यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।

कछ अलग के नाम पर भले ही हम रेस्टोरेंट का खाना खा लें, पर सुकून और स्वाद तो घर के खाने से ही मिलता है। घर का बना खाना हम भारतीयों के लिए क्यों है इतना खास, इस बात की पड़ताल कर रही हैं नेहा...

क्षमता में इजाफा तो हुआ है, पर साथ ही सेहत को लेकर सतर्कता भी बढ़ी है। घर के खाने को लेकर बरकरार इस रुझान के लिए यह कारण काफी हद तक जिम्मेदार है। और जब कोई आफकी हाथों के बने खाने की तारीफ करता है, तो यकीन मानिए उससे बेहतर फीडबैक कुछ और नहीं हो सकता।' **कुकिंग के शौक ने बना दी कम्प्यूनिटी :** रसोई की सीमाओं के आगे कुकिंग ने महिलाओं को अपनी एक अलग कम्प्यूनिटी बनाने का भी मौका दिया है। घर के बने खानपान को बढ़ावा देने के लिए होने वाले इस आयोजन को नाम दिया गया है-फूड पॉप अप्स और क्लाउड किचन। इन फूड पॉप अप्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें से अधिकांश क्षेत्रीय खानपान को बढ़ावा देते हैं। गुरुग्राम में 'मारवाड़ी' खाना के नाम से लोगों को खाना परोसने वाली और फाइव स्टार होटल में अपना फूड पॉप अप्स आयोजित करने वाला अभिलाषा जैन कहती हैं, 'हमारे घरों में कुकिंग का उत्सव मनाया जाता है। खाने से हमारा एक भावनात्मक संबंध होता है। पीढ़ियों से हमारे घरों में न सिर्फ तरह-तरह का खाना बनाया जाता है बल्कि उसकी तारीफ भी की जाती है। मैं एक मारवाड़ी परिवार से आती हूं, जहां मैंने हर चीज घर में बनते देखा है।

आज मैं उसी परंपरा को अपनी कुकिंग के माध्यम से बढ़ा रही हूं। फूड पॉप के माध्यम से मैं और मेरे जैसे सैकड़ों शेफ घर का बना खाना टेबल पर लेकर आ रहे हैं। हम वही परोस रहे हैं, जो हम खुद खाते हैं। हम वही सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, जो घर के लिए खाना बनाते वक्त करते हैं। खाने की फ्रेशनेस, सामग्री की गुणवत्ता और अपने इलाके के खाने के स्वाद को बरकरार रखने की हमारी कोशिश ही हम सभी होम शेफ को खास बनाती है। हम सालों की रेसिपी को इस्तेमाल में ला रहे हैं। और हम जब उसे परोसते हैं तो वह स्वाद उसमें झलकता है। होम शेफ की हमारी कम्प्यूनिटी साथ मिलकर पारंपरिक और क्षेत्रीय खानपान को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।' कई होम शेफ इस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप की मदद से फूड पॉप अप्स का अपना यह काम कर रहे हैं।

HEALTH

हमारे खानपान की आदतें हमें सेहतमंद रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। अगर आप वजन घटाने की कोशिश में लगी हैं, तो घर का बना खाना ही खाएं। क्यों? बता रही हैं एक्सपर्ट...



तो बहुत होती है। पर, कभी सोचा है कि आपका वह ऑर्डर आपके शरीर को खुशी देता है कि नहीं? बाहर के खाने में घर के खाने की तुलना में कैलोरी और नुकसान दोनों ही ज्यादा होते हैं। एक अध्ययन की मानें तो रेस्टोरेंट के औसतन घर, भोजन में 1327 कैलोरी होती है, जबकि आप घर पर खाने की सर्विंग में कैलोरी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकती हैं।

ट्रांस फैट करता है नुकसान : रेस्टोरेंट के खाने में कई बार गर्म हुआ तेल भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिसका आपका अंदाजा भी नहीं होता। बार-बार गर्म हुए तेल में एलडीएल का स्तर बढ़ जाता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसकी अधिकता हृदय रोग, स्ट्रोक, सीने में दर्द के खतरे को बढ़ा देता है। बार-बार गर्म हुए तेल का सेवन करने से एसिड की मात्रा भी बढ़ जाती है। सूरजमुखी, मकई के तेल

जैसे कुछ वैजिटेबल ऑयल को दोबारा गर्म करने से उसमें जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ सकती है। जिससे हृदय रोग, अल्जाइमर, डिमेंशिया और पार्किंसंस सरीखी स्थितियां बन सकती हैं। वैजिटेबल तेल को दोबारा गर्म करने पर एनएई नाम का एक और जहर निकलता है, जो डिएनए, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को किसी तरीके से काम करने से रोकता है। दोबारा गर्म हुए तेल में पका खाना कांसिनोजेनिक भी हो सकता है। यानी कैंसर का कारण बन सकता है। बेहतर होगा कि आप घर में शुद्ध तेल में पका भोजन ही नियमित रूप से खाएं।

नहीं रहता नियंत्रण : बाहर की रसोई में पके खाने पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। कई बार पसंदीदा पकवान को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें कुछ ऐसी चीजों को साथ में डाल दिया जाता है, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। कई बार खाने के गलत कॉम्बिनेशन जैसे- मछली के साथ दूध, दूध और नींबू, दही के साथ फल, बींस और चीज, गर्म चीजों के साथ शहद, फलों के साथ डेयरी प्रोडक्ट, मूली और दूध, प्रोटीन के साथ स्टार्च वगैरह का इस्तेमाल होता है, जिसका हमें अंदाजा नहीं लग पाता। हम स्वाद के फेर में गलत कॉम्बिनेशन को खा लेते हैं, जिसका असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है।

नहीं पता होता ताजे-बासी का फर्क : जब आप बाहर खाना खाती हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपको ताजा खाना परोसा जा रहा है या फिर बासी। पर, बाहर का बासी खाना फूड पॉइजनिंग, पाचन संबंधी, संक्रमण, कफजोर इन्फ्यूनिटी सरीखी समस्याओं को दावत देता है। लिहाजा, बेहतर होगा कि आप बाहर की जगह घर पर बना ताजा खाना खाएं। खासतौर पर चावल। जब उसे आप काफी देर तक रख कर उसे दोबारा इस्तेमाल करती हैं तो वह संक्रमित हो जाता है, जिसे फ्राइड राइस सिंड्रोम कहा जाता है। यह आपके पेट से लेकर कई तरह की बीमारियों की वजह बन सकता है। बासी चावल दिल से जुड़ी बीमारियों का भी कारण बन सकता है।

डिस्कलेमर : यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।

हरित भविष्य को सशक्त बनाना : मोदी सरकार के 11 वर्षों ने भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को कैसे बदल दिया

“प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत ने न केवल अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, बल्कि हमने दृढ़ संकल्प, नवाचार और बेजोड़ प्रदर्शन के साथ उन्हें हासिल भी किया है।”

सौर ऊर्जा में तीसरे, पवन ऊर्जा में चौथे और कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मंत्र चौथे स्थान के साथ, आज भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। 232 गीगावाट से अधिक स्थापित और 176 गीगावाट निर्माणाधीन नवीकरणीय क्षमता होने के साथ, हम न केवल अपनी ऊर्जा से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि ऊर्जा में बदलाव से जुड़ी वैश्विक चर्चा को सक्रिय रूप से आकार दे रहे हैं। यह प्रगति संयोग नहीं है, बल्कि यह पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार किए गए साहसिक सुधारों, समयबद्ध फैसलों और स्पष्ट दीर्घकालिक दृष्टिकोण का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास एक मजबूत नवीकरणीय ऊर्जा इकोसिस्टम बनाने का एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा को वैश्विक प्राथमिकता बनने से बहुत पहले बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं का बीड़ा उठाया था। 2014 में पदभार संभालने के बाद, उन्होंने उस विजन को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया। नतीजतन, आज भारत सौर, पवन और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े नवाचार में एक वैश्विक लीडर के रूप में खड़ा है।

पिछले वर्ष में ही, हमने राष्ट्रीय ग्रिड में रिकॉर्ड 29 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ी। सौर ऊर्जा क्षमता 2014 के सिर्फ 2.63 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 108 गीगावाट से अधिक हो गई है, जो 41 गुना की आश्चर्यजनक वृद्धि है। पवन ऊर्जा क्षमता भी 51 गीगावाट को पार कर गई है। देश भर

में फैली इन परियोजनाओं को अब एकीकृत पारेषण प्रणाली के माध्यम से एक साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे एक राष्ट्र एक ग्रिड (वन नेशन वन ग्रिड) का सपना साकार होगा, जहां प्रत्येक भारतीय, चाहे वह किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो, विश्वसनीय बिजली प्राप्त कर सकेगा। लेकिन इस बदलाव के स्तर को समझने के लिए हमें यह याद रखना होगा कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। वर्ष 2014 में भारत का बिजली क्षेत्र गहरे संकट से जूझ रहा था। बिजली की कमी लगातार बनी हुई थी। 2012 में डबल ग्रिड फेलियर हुआ, जिसने हमसे पहले उत्तरी क्षेत्र को 36,000 मेगावाट लोड की हानि के साथ प्रभावित किया और बाद में उत्तरी, पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी ग्रिडों के ध्वस्त होने का कारण बना, जिससे 48,000 मेरुआत कहाँ से की थी। वर्ष 2014 में भारत की हमारी यादों में ताजा है। पारेषण इंफ्रास्ट्रक्चर पर अत्यधिक बोझ था और निवेशकों का भरोसा कम था। नवीकरणीय ऊर्जा को महंगा और अविश्वसनीय माना जाता था। वैश्विक समुदाय ने भारत को एक गंभीर स्वच्छ ऊर्जा खिलाड़ी के रूप में नहीं देखा। वहाँ, देश के भीतर, जनता की अपेक्षाएं मामूली थीं। नीतिगत अनिर्णायकता की स्थिति के चलते भी भारत को 'नाजुक पांच' अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में गिना जाता था।

वह परिदृश्य निर्णायक रूप से बदल गया है। भारत ऊर्जा की कमी से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गया है। पिछड़ने की स्थिति से उबरते हुए, अब हम मिसाल के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं।

यहां, मैं मोदी सरकार के तहत पिछले 11 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में किए गए 11 परिवर्तनकारी सुधारों पर प्रकाश डालता हूँ, जिनमें से प्रत्येक आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सबसे पहले, फीड-इन टैरिफ

से पारदर्शी, बाजार-संचालित बोली प्रक्रिया में बदलाव ने एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। प्रतिस्पर्धी बोली और टैरिफ युक्तिकरण के कारण सौर टैरिफ 2010 में ₹10.95 प्रति यूनिट से गिरकर 2021 तक आश्चर्यजनक रूप से ₹1.99 प्रति यूनिट रह गया, जिसने भारत को सौर ऊर्जा में मूल्य के मामले में वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित किया। इस सुधारों ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया और जीवाश्म ईंधन के साथ मूल्य के मामले में समानता स्थापित की है।

दूसरा, अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएम) शुल्कों की छूट एक और प्रमुख कदम रहा है। इन शुल्कों को हटाकर, सरकार ने परियोजना डेवलपर्स के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक को समाप्त कर दिया। अपतटीय पवन के लिए 2032 तक और हरित हाइड्रोजन के लिए 2030 तक विस्तारित, इस नीति ने भौगोलिक सीमाओं से नवीनीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन को प्रभावी रूप से मुक्त कर दिया और पूरे भारत में ऊर्जा प्रवाह को प्रोत्साहित किया।

तीसरा, आयात पर निर्भरता कम करने और रोजगार सृजन के लिए सरकार ने 24,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के साथ सौर विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की। इससे घरेलू विनिर्माण में उछाल आया है, जो 2014 की 2.3 गीगावाट से बढ़कर मांड्रूल में 88 गीगावाट और 2025 तक सेल क्षमता में 0 से 25 गीगावाट हो गया है। भारत अब केवल सौर ऊर्जा का उपयोग ही नहीं कर रहा है, बल्कि इसे बना भी रहा है। इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होती है और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है।

ड्रोन और उसके कलपुर्जों के लिए दो विशेष पीएलआई योजनाओं की शुरुआत से अगली पीढ़ी के नवाचार को और भी बढ़ावा मिला है। आज, भारत द्वारा डिजाइन की गई मिसाइल प्रणाली, बख्तरबंद वाहन और नौसैनिक प्लेटफॉर्म न केवल हमारी सेनाओं में तैनात हैं, बल्कि 80 से अधिक देशों को निर्यात किए गए हैं। इससे ऐसे समय में क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की छवि मजबूत हुई है, जब विश्वसनीय रक्षा भागीदारों पर वैश्विक भरोसा बहुत अधिक है। विनिर्माण इसी नजरिये के केंद्र में है। भारत बड़े निवेश और सरकारी प्रोत्साहनों के कारण सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असम में ₹27,000 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र बना रहा है, जिसके 2025 के मध्य तक परिचालन में आने और लगभग 27,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इस बीच, एचसीएल और फॉक्सकॉन का ₹3,706 करोड़

का संयुक्त उद्यम उत्तर प्रदेश के जेवर में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए तैयार है, जो डिस्प्ले ड्राइवर चिप पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसका उत्पादन 2027 में शुरू होगा। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 1.57 लाख से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। इनमें 100 से ज्यादा यूनिकर्न और 3,600 से ज्यादा डीप-टेक वेंचर शामिल हैं जो एआई, बायोटेक और सेमीकंडक्टर पर केंद्रित हैं। अकेले हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र में 200 से ज्यादा स्टार्टअप सामने आए हैं, जो एक भरोसेमंद इनोवेशन अर्थव्यवस्था के उदय का संकेत है। स्टार्टअप इकोसिस्टम ने पहले ही 17.2 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं और समस्या-समाधानकर्ताओं (प्रॉब्लम सॉल्वर्स) एवं उद्यमियों की एक नई

तकनीकी और रणनीतिक श्रेष्ठता देखी है। दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति आत्मनिर्भरता के लिए रणनीतिक निवेश से मेल खाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की व्यापक सटीकता, आंशिक रूप से कई वर्षों तक स्वदेशी रक्षा क्षमता पर लगातार ध्यान केंद्रित करने के कारण सक्षम हुई। 2014 के बाद, भारत के रक्षा विनिर्माण का तेजी से आधुनिकीकरण हुआ है, निर्यात में भारी बढ़ोतरी हुई है। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी), रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति (डीपीडीपी) जैसे प्रमुख सुधार और कुछ क्षेत्रों के लिए 100% एफडीआई खोलने से घरेलू कंपनियों को फलने-फूलने में मदद मिली है।

संयुक्त उद्यम उत्तर प्रदेश के जेवर में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए तैयार है, जो डिस्प्ले ड्राइवर चिप पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसका उत्पादन 2027 में शुरू होगा। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 1.57 लाख से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। इनमें 100 से ज्यादा यूनिकर्न और 3,600 से ज्यादा डीप-टेक वेंचर शामिल हैं जो एआई, बायोटेक और सेमीकंडक्टर पर केंद्रित हैं। अकेले हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र में 200 से ज्यादा स्टार्टअप सामने आए हैं, जो एक भरोसेमंद इनोवेशन अर्थव्यवस्था के उदय का संकेत है। स्टार्टअप इकोसिस्टम ने पहले ही 17.2 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं और समस्या-समाधानकर्ताओं (प्रॉब्लम सॉल्वर्स) एवं उद्यमियों की एक नई

चौथा, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार ने मांड्रूल और विनिर्माताओं की स्वीकृत सूची (एएलएमएम), घटकों और विनिर्माताओं की स्वीकृत सूची (एएलसीएम) के साथ-साथ घरेलू सामग्री आवश्यकताओं (डीसीआर) को लागू किया, जिससे गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति श्रृंखला की संपूर्णता सुनिश्चित हुई और आयातित सौर घटकों पर निर्भरता कम हुई। इन उपायों ने भारतीय निर्माताओं के लिए एक समान अवसर तैयार किए हैं, जिससे एक लचीले और प्रतिस्पर्धी सौर इकोसिस्टम का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

पांचवां, प्रधानमंत्री के विजन के तहत, पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना एक परिवर्तनकारी पहल बन गई है, जिसका लक्ष्य 30 गीगावाॉट की विकेंद्रीकृत क्षमता तैयार करने के लिए एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करना है। लगभग 13.75 लाख घरों को पहले ही इससे जोड़ा जा चुका है, जिससे जमीनी स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच का

बदलाव आ रहा है। इसी तरह, पीएम-कुसुम योजना किसानों के विकेंद्रीकृत सौर प्रणाली लगाने में सक्षम बनाकर कृषि को सौर ऊर्जा से लैस कर रही है। 11 लाख से अधिक पंपों को सौर ऊर्जा से युक्त किया गया है, जिससे भारत का ये सबसे अधिक ऊर्जा-गहन क्षेत्र जलवायु सहयोगी में बदल गया है।

सातवां, भारत अब स्वच्छ ऊर्जा के मामले में दुनिया का अनुसरण नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। 2014 में एफडीआई के मामूली प्रवाह से, भारत ने अप्रैल 2020 से सितंबर 2024 के दौरान आरई \$ में \$19.98 बिलियन का

पीढ़ी को प्रेरित किया है।

इस बीच, भारत धीरे-धीरे दुनिया के सबसे जुड़े हुए लोकतंत्र के रूप में उभरा है। 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स और 136 करोड़ आधार नामांकन के साथ, यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम बन गया है। अब हमारी वैश्विक डिजिटल पेमेंट में 46% हिस्सेदारी हो गई है, जो यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिसने वित्तीय लेन-देन को सभी के लिए आसान बना दिया है। इन प्रणालियों ने न केवल नागरिकों को सशक्त बनाया है बल्कि शासन को और भी स्मार्ट, तेज और पारदर्शी बनाया है।

2024-25 के केंद्रीय बजट में हमारी सरकार की निर्णय लेने की क्षमता साफ नजर आती है। कुल व्यय ₹44.6 लाख करोड़ निर्धारित किया गया, जिसमें पूंजीगत व्यय को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाकर ₹10 लाख करोड़ किया गया। कर छूट को बढ़ाया गया, मध्यम वर्ग के लिए रिबेट दोगुनी कर दी गई और लंबे समय से स्टार्टअप के लिए चिता का विषय रहे एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया। इन सुधारों से उपभोग में बढ़ोतरी होती है, उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है और भारत के दीर्घकालिक विकास पथ को मजबूती मिलती है।

मोदी 3.0 के एक साल पूरे होने पर, बदलाव स्पष्ट नजर आ रहा है। सड़कें, कारखाने और सौर पैनल सिर्फ प्रगति के संकेत नहीं हैं, बल्कि वे आकांक्षाओं की नींव हैं। आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक सहित हर क्षेत्र में भारत राष्ट्रीय स्तर पर नवीनीकरण का एक नया अध्याय लिख रहा है। जनादेश भी स्पष्ट है। विजन बकरार है। और, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, निर्णायक दशक अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। इतिहास इस वक्त को सिर्फ तेज विकास के चरण के रूप में ही नहीं, बल्कि उस क्षण के रूप में दर्ज करेगा, जब भारत ने विश्वास किया, बदलाव किया और नेतृत्व किया है।

एफडीआई आकर्षित किया, जो आज भारत में एफडीआई आकर्षित करने वाले शीर्ष क्षेत्रों में से एक के रूप में उभर रहा है। इससे देश के वैश्विक स्तर पर बढ़ते कद और आर्थिक क्षमता का पता चलता है। इस यात्रा में एक अन्य प्रमुख उल्टेरक लगभग ₹20,000 करोड़ के निवेश समर्थन वाला राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ ईंधन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है।

आठवां, पारेषण इंफ्रास्ट्रक्चर इस बदलाव की रीढ़ बना हुआ है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और 2030 ट्रांसमिशन (पारेषण) रोडमैप में भारत का निवेश सुनिश्चित करता है कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं ग्रिड से कुशलतापूर्वक और विश्वसनीय तरीके से जुड़ सकें। यह पहल कटौती के जोखिम को कम करती है और ग्रिड स्थिरता को बढ़ाती है। नौवां, सरकार भारत के समुद्र तट की विशाल क्षमता का भी दोहन कर रही है। 2030 तक 37 गीगावाॉट की निविदाओं को सौर ऊर्जा के साथ अपतटीय पवन (ऑफशोर विंड) पहल को व्यवहार्यता अंतर निधि और मजबूत साइट सर्वेक्षणों द्वारा समर्थित किया जा रहा है। गुजरात और तमिलनाडु में पायलट परियोजनाएं पहले से ही भारत के अगले अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की नींव रख रही हैं। दसवां बात, बिजली आपूर्ति में रुकावट की चुनौती को पहचानते हुए भारत ने हाइब्रिड और चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने की नीति के साथ निर्णायक कदम उठाया है। पवन-सौर हाइब्रिड और टोस एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआई) को बढ़ावा देकर भारत चौबीसों घंटे स्वच्छ ऊर्जा समाधान तैयार कर रहा है। पाइपलाइन में 65 गीगावाट से अधिक क्षमता के साथ, यह ग्रिड की विश्वसनीयता और जीवाश्म-आधारित बेसलोड बिजली के विकल्प के लिए महत्वपूर्ण है।

कमांड अस्पताल चंडीमंदिर ने कारगिल की अधिक ऊंचाई से आपातकालीन स्थिति में पहुंचे सैनिक की जान बचाई


 जालंधर ब्रीज :

चिकित्सा विशेषज्ञता का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए, पश्चिमी कमान के चंडीमंदिर कमांड अस्पताल ने एक सेवारत सैनिक की जान बचाई, जिसे कारगिल की ऊंचाई से जोजिखम वाली स्थिति में एयरलिफ्ट करके लाया गया था।

यह सैनिक, जो गंभीरता से श्वास लेने में असमर्थता का अनुभव कर रहा था, जिसे अधिक ऊंचाई से संबंधित एक आपातकालीन स्थिति द्विपक्षीय पल्मोनरी श्रोम्बोम्बोलिज़्म रोग के लक्षण बताए गए , का कमांड अस्पताल द्वारा निवारण किया गया। लेंप्टिनेंट कर्नल पुरुषोत्तम के नेतृत्व में चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम ने समय पर निदान और आपातकालीन उपचार प्रदान

किया, जिसमें थक्का (क्लाट) विघटन इलाज भी शामिल था। तुरंत कार्रवाई द्वारा रोगी की जान बचाई जा सकी, और वह वर्तमान में स्थिर है और ऑक्सीजन की सहायता से ठीक हो रहा है।

उल्लेखनीय है के कल आपातकाल स्थिति में सैनिक को कारगिल से कमांड अस्पताल चंडीमंदिर तक तत्परता दिखाते हुए भारतीय वायु सेना के एएन-32 विमान द्वारा सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट करके पहुंचाया गया था।

यह उपलब्धि कमांड अस्पताल द्वारा प्रदान की गई असाधारण चिकित्सा देखभाल का प्रमाण है, जो जीवन रक्षण और राष्ट्र की सेवा करने वालों को सुविधा प्रदान करने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संकल्प से सिद्धि : मोदी युग ने गढ़ी नए भारत की सशक्त, सुरक्षित और विकसित तस्वीर

वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब भारत एक अहम मोड़ पर खड़ा था। एक ऐसा देश, जहां आकांक्षाएं तो थीं लेकिन उनके पूरे होने की दिशा स्पष्ट नहीं थी। लेकिन बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस दिशा और गति से विकास की यात्रा तय की है, वह आज 'न्यू इंडिया' के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है। आज भारत आत्मविश्वास से भरा, आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर और वैश्विक मंच पर अपनी स्पष्ट आवाज रखने वाला राष्ट्र है।

इस बदलाव की शुरुआत गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने से हुई। आजादी के छह दशकों बाद भी भारतवासी घर, शौचालय, जल और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। इस दिशा में पहल करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर और शौचालय बनाकर दिए गए। उज्ज्वला योजना के माध्यम से निशुल्क गैस कनेक्शन देकर करोड़ों महिलाओं को धूप से मुक्ति दिलाई जबकि आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं ने गरीबों को 15 लाख तक की बीमा सुरक्षा देकर उन्हें आर्थिक आपदा से बचाया। हर घर जल अभियान के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया। ये योजनाएं सिर्फ कागजों की नीतियां नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत में तब्दील होकर आम जनजीवन को बदल चुकी हैं। जन धन योजना के माध्यम

से आजादी के बाद पहली बार करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया, जिससे देश में आर्थिक समावेशन को मजबूती मिली है। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी भारत ने ऐतिहासिक प्रगति की है। जिन गांवों में कभी बिजली और पक्की सड़कें एक सपना हुआ करती थीं, वहां अब सोलर लाइटें जलती हैं। दूर-दराज गांवों की राष्ट्रीय राजमार्गों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा चुकी है। शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन और मेट्रो परियोजनाओं ने जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है।

भारत की यह विकास यात्रा डिजिटल रूप से भी क्रांतिकारी रही है। डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया और यूपीआई ने आज भारत को दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल लेन-देन करने वाला देश बना दिया है। आधार, मोबाइल और जनधन की 'त्रिमूर्ति' ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को सहज बनाते हुए भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका को लगभग समाप्त कर दिया। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। महिला सशक्तिकरण नरेन्द्र मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में रहा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर मातृत्व अवकाश में वृद्धि और सुकुन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं ने महिलाओं और बेटियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त किया है। एनडीए और भारतीय सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन जैसी पहलों ने यह साबित किया कि



सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण केवल स्लोगन नहीं, बल्कि नीति और नीयत दोनों का हिस्सा बन चुका है। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद देश का कृषि क्षेत्र लंबे समय तक उपेक्षित रहा, सरकारों के तमाम कागजी दावों के उलट स्थिति ये थी कि किसान खेती छोड़कर नौकरी के लिए पलायन करने को मजबूर थे। बीते एक दशक में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आए। आज पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के हर छोटे किसान को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जा रही है। फसल बीमा योजना, ई-नाम पोर्टल, माइक्रो सिंचाई योजनाएं, और ड्रोन टेक्नोलॉजी के प्रयोग ने कृषि को सिर्फ उपज की दृष्टि से नहीं, बल्कि आय के स्रोत के रूप में मजबूत किया गया है। इसी तरह शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी कई ऐतिहासिक पहल की गईं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में गुणात्मक

परिवर्तन आए। मातृभाषा में पढ़ाई को बढ़ावा, कौशल आधारित शिक्षा और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा, स्वयं, और पीएम ई-विद्या ने शिक्षा को अधिक सुलभ और समावेशी बनाया है। स्किल इंडिया के अंतर्गत लाखों युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे युवा अब नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले बन रहे हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान जो साहसिक और तेज निर्णय लिए, वे पूरी दुनिया में सराहे गए। स्वदेशी वैक्सीन निर्माण और कोविन पोर्टल का सफल संचालन यह दर्शाता है कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, तकनीक और विज्ञान का निर्माता भी है। साथ ही फिट इंडिया, योग दिवस और आयुष मंत्रालय की सक्रियता ने भारतीय जीवनशैली को फ़िर से प्रासंगिक बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी की 'लोकल को ग्लोबल' बनाने की दूरदर्शी सोच ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से घरेलू उद्योगों और नवाचारों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उतारने की शक्ति दी है। भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, और पीएलआई स्क्रीम जैसे प्रोत्साहनों मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और रक्षा विनिर्माण में भी भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है।

दशकों तक बुनियादी ढांचा निर्माण के क्षेत्र में उस प्रगति से कायं नहीं हुए जिसकी देश को जरूरत थी। बीते एक दशक में भारत माला, सागर माला, और

उड़ान जैसी योजनाओं ने देश के दूरस्त इलाकों को सड़क, रेल, जल और वायु मार्गों से जोड़ने में नई ऊंचाई दी है। वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और रेलवे के विद्युतीकरण से न केवल यात्रा की गति बढ़ी है, बल्कि यात्रा को पर्यावरण के अनुकूल भी बनाया गया है। रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने अभूतपूर्व आत्मनिर्भरता दिखाई है। दशकों से लंबित वन रैंक, वन पैपन लागू हुआ, ब्रह्मोस, आकाश जैसे रक्षा उपकरणों से सेनाओं की न सिर्फ़ ताकत बढ़ी बल्कि भारत दुनिया में हथियार निर्यात भी कर रहा है। विक्रान्त का निर्माण, अग्नि मिसाइलों की श्रृंखला और सीमा पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण भारत की सुरक्षा प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

एक ओर जहां आर्थिक और तकनीकी विकास हुआ, वहीं सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण की भी समाज में नई चेतना पैदा की है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि, मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और केदारनाथ पुनर्निर्माण जैसे प्रकल्पों ने सांस्कृतिक अस्था को सम्मान और भव्यता दोनों दिए है। योग दिवस को वैश्विक मान्यता दिलाकर भारत ने पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन से जोड़ने का भी कार्य किया है। स्वच्छता की नई क्रांति लाई। भारत अब नए ज़ीरो 2070 के लक्ष्य की ओर कार्यरत है, और सौर ऊर्जा व इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों

में भी भारत ने पहली बार 'फॉलोवर' से 'लीडर' की भूमिका निभाई है। ८20 की अय्यक्षता, वैक्सीन मैत्री, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वाईस ऑफ़ ग्लोबल साउथ जैसे प्रयासों ने भारत को विकासशील देशों का नेतृत्वकर्ता बना दिया है। भारत अब संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता की दिशा में गंभीर दावेदारी कर रहा है। नरेन्द्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता उसकी राजनीतिक इच्छाशक्ति रही है, चाहे वह धारा 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय हो, तीन तलाक जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करना हो, या एक देश-एक कर जैसी जटिल लेकिन आवश्यक व्यवस्था को लागू करना हो। पारदर्शी शासन और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर देश में 'अंत्योदय' को व्यवहारिक रूप दिया गया है।

आज जब बीते 11 वर्षों की ओर पीछे देखें, तो यह स्पष्ट दिखता है कि यह केवल योजनाओं की सूची नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण की जीवत तस्वीर है। यह कालखंड केवल आर्थिक या भौतिक उपलब्धियों का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरूकता का युग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का संकल्प लिया था वह अब सिर्फ़ एक नारा नहीं, भारत की पहचान बन चुका है। यह सिद्धि केवल सरकार की नहीं, हर उस नागरिक की है जिसने इस संकल्प में आस्था रखी और यही 21वीं सदी के भारत का असली परिचय है।

पंजाब सरकार ने घटिया दर्जे की नॉर्मल सलाइन सप्लाई करने के आरोप में कैप्टेब बायोटेक कंपनी पर 3 साल के लिए लगाई रोक

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह- अमृतसर और संगरूर के अस्पतालों में मरीजों को रिएक्शन होने की रिपोर्ट मिलने के बाद की गई सख्त कार्रवाई

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने फार्मा कंपनी मैसर्स कैप्टेब बायोटेक, सोलन द्वारा घटिया दर्जे की आईवी फ्लूइड या नॉर्मल सलाइन पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन (पीएचएससी) को सप्लाई करने के आरोप में उक्त कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। आज यहां पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कंपनी पर पंजाब सरकार के किसी भी टेंडर में हिस्सा लेने से तीन साल के लिए रोक लगा दी गई है। इसके अलावा पीएचएससी को सप्लाई की जा रही 11 वस्तुओं की कीमत संबंधी सभी कॉन्ट्रैक्ट भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, "कंपनी की 3,30,000 रुपये



की परफॉर्मेंस सिस्कोरिटी रकम जब्त कर ली है और बकाया भुगतान रोक दिए गए हैं।"

मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करने के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन

(सीडीएससीओ) के पास यह मामला उठाने के बाद, अथॉरिटी द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए कंपनी के सभी निर्माण/उत्पादन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। यह कार्रवाई अमृतसर और संगरूर के सरकारी अस्पतालों में कुछ मरीजों को मैसर्स कैप्टेब बायोटेक द्वारा तैयार की गई नॉर्मल सलाइन के उपयोग के कारण हुए एडवर्स ड्रग रिएक्शन (एडीआर) के बाद अमल में लाई गई है। तुरंत कार्रवाई करते हुए, डीएचएस पंजाब ने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य को मुख्य रखते हुए उक्त नॉर्मल सलाइन के पूरे स्टॉक को फ्रीज कर दिया था और पीएचएससी ने कंपनी द्वारा सप्लाई किए गए सभी स्टॉक को वापस मंगवा लिया था। डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि एफडीए पंजाब और सीडीएससीओ, नई दिल्ली की संयुक्त टीम द्वारा उक्त नॉर्मल सलाइन के नमूने लिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया

कि पीएचएससी द्वारा राज्य भर की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं से नॉर्मल सलाइन का सारा स्टॉक कंपनी द्वारा अपने खर्च पर वापस मंगवाने के निर्देश दिए जाने के उपरांत उक्त कंपनी ने सारा बचा हुआ स्टॉक वापस मंगवा लिया था।

उन्होंने आगे बताया कि विभाग द्वारा तीन लैबों, जिन्होंने पहले इस कंपनी के नमूनों को पास किया था और बाद में जिन्हें 'गैर-मानक' घोषित कर दिया गया है, की भूमिका की जांच की जा रही है।

भारतीय मौसम विभाग द्वारा पंजाब के लिए जारी की गई गंभीर गर्मी की चेतावनी के मद्देनजर, डॉ. बलबीर सिंह ने एक पब्लिक एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें सभी नागरिकों को अत्यधिक गर्मी से अपने-आप को बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की गई है। उन्होंने बार-बार पानी पीने और बाहर निकलते समय पानी

साथ रखने की महत्ता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नवजात बच्चों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, मोटापे या मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और दिल की बीमारियों या पुरानी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों सहित संवेदनशील समूहों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

उन्होंने आगे बताया कि सीधी धूप में काम करने वाले मजदूर, निर्माण कर्मी और गलियों में फेरी वाले व्यक्तियों को ख़ास तौर पर गर्मी से खतरा होता है और उन्हें छायादार क्षेत्रों में आराम करना चाहिए और गर्मी के चरम समय में नियमित रूप से पानी पीना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य वासियों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बाहरी गतिविधियों से बचने, हल्के, ढीले सूती कपड़े पहनने और बाहर निकलते समय टोपियों, पगड़ियों या दुपट्टे से अपने सिर ढकने की सलाह दी।

जालंधर में ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के 103 दिन, 577 तस्करों को ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार

पुलिस कमिश्नर ने कहा- 10 अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया, 258 व्यक्तियों को नशा मुक्ति केंद्रों में भेजा

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

पंजाब सरकार द्वारा राज्य से नशे को खत्म करने के लिए शुरू किए गए ‘ युद्ध नशे के विरुद्ध ’ अभियान ने आज 103 दिन पूरे कर लिए हैं। इस अनूठी पहल के तहत पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 410 मामलों में 577 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में नशे की खेप जब्त की है। इन बरामदगी में 50.150 किलोग्राम चूरा पोस्त, 24.935 किलोग्राम हेरोइन, 1.161 किलोग्राम चरस, 3.720 किलोग्राम गांजा, 9,668 कैप्सूल/गोलियां, 3,30,700 रुपये ड्रग मनी, छह पिस्तौल और 14 कारतूस शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शहर भर में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार की जा रही कार्रवाई के सार्थक



परिणाम सामने आए हैं, जिसके तहत बड़े पैमाने पर बरामदगी और गिरफ्तारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि यह सभी प्रयास मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के राज्य को रंगला पंजाब बनाने के सपने को साकार करने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने शहर से नशे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जालंधर पुलिस कमिश्नरेट की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नशा

तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने नशा तस्करों द्वारा विशेष रूप से ड्रग मनी से बनाए गए अवैध ढांचों/कब्जों को ध्वस्त करने में नागरिक प्रशासन की मदद की है। सिविल प्रशासन द्वारा पुलिस की मदद से दस से अधिक ऐसे ढांचों को ध्वस्त किया जा चुका है। इसी तरह इस अभियान के अंतर्गत जालंधर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा लगभग 11 फरार अपराधियों को सफलतापूर्वक पकड़ा गया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि राज्य सरकार राज्य से नशे के ख़ात्मे के लिए प्रवर्तन, नशामुक्ति और रोकथाम की त्रि-आयामी नीति लागू कर रही है और 'नशा मुक्ति' प्रयासों के तहत कमिश्नरेट पुलिस ने 1 मार्च, 2025 से 11 जून, 2025 के बीच 'युद्ध नशे के विरुद्ध ' के तहत 258 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है।

डिटी कमिश्नर द्वारा नशा मुक्ति केंद्र का दौरा, 25 और बैडों की सुविधा जल्द



• **जालंधर ब्रीज.** कपूरथला

डिप्टी कमिश्नर कपूरथला अमित कुमार पंचाल ने आज जिला सिविल अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र का दौरा किया। उन्होंने केंद्र के कामकाज का जायजा लिया और निर्देश दिए कि नशा मुक्ति केंद्र में आने वाले मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नशे को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने

कहा कि जल्द ही इस नशा मुक्ति केंद्र को अपडेट करके 25 बैडों की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस अवसर पर एडीसी नवनीत कौर बल, एसीएस डॉ. अनू शर्मा, एस.एम.ओ डॉ. इंदु बाला, डॉ. अमन सुद, सुपरिटेडेंट राम अवतार और विभिन्न विभागों से आए अधिकारी मौजूद थे।

डिटी कमिश्नर आशिका जैन ने क्रशर व जमीन मालिकों को खनन नीति के बारे में किया जागरूक

• **जालंधर ब्रीज.** होशियारपुर

पंजाब सरकार के खान एवं भूविज्ञान विभाग की ओर से जारी पंजाब स्टेटे माइनर मिनरल (संशोधन) पाॉलिसी-2025 के तहत जिला स्तर पर संबंधित पक्षों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासनिक पर्सिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक की अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, खनन कार्य से जुड़े क्रैशर व जमीन मालिकों ने भाग लिया। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि राज्य में गैर कानूनी माइनिंग रोकने व रेत और बजरी की कीमतें और कम करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से इस पालिसी में संशोधन किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने नई नीति